RNI NO.- MPBIL/2020/79198

उद्घोष समय

वर्ष 05 अंक 76 | सतना, शुक्रवार 05 सितंबर,2025 | पृष्ठ: 4, मूल्य : 1 रूपए

अमेरिकी कोर्ट के सामने बहाना बनाने में जुटे ट्रंप, भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर बोले- जरूरी था

नई दिल्ली एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार (4 सितंबर 2025) को सुप्रीम कोर्ट में संघीय अदालत के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी आयात पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। यहां ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को उचित ठहराते हुए कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। अमेरिकी सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया, राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन में जारी युद्ध से निपटने के लिए रूसी एनर्जी की खरीद पर भारत के खिलाफ इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट टैरिफ लगाया है। यह युद्धग्रस्त देश में शांति के प्रयास के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करने का अधिकार है। ट्रंप के खिलाफ अपील में कहा गया, टैरिफ वाले फैसले से विदेश नीति खतरे में आ गई है। दूसरे देशों के साथ वार्ता पर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। इससे पहले से तय किए गए फ्रेमवर्क डील और वार्ता खतरे में है।यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि अमेरिका यह मुकदमा हार जाता है तो उसे यूरोपीय यूनियन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के साथ किए गए व्यापार समझौतों को रद्द करना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस हार से अमेरिका को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, हमने यूरोपीय यूनियन के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वे हमें लगभग एक ट्रिलियन डॉलर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इन्हें रद्द करना होगा। हमारे देश के पास फिर से और अधिक समृद्ध होने का मौका है। हमारा देश फिर से गरीब भी हो सकता है। अगर हम यह मुकदमा नहीं जीतते हैं तो हमारे देश का भारी नुकसान होगा।

रोटी, पराठा, दूध, हेल्थ-लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री

GST के अब केवल दो स्लैब 5% और 18% ; 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव

नई दिल्ली एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई। इस दौरान बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री ने गुड्स और सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। काउंसिल ने मौजूदा 12 फीसदी और 18 फीसदी दरों को हटा दिया है। इसके साथ ही अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी को मंजूरी दे दी गई है।

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में दो दरों वाली जीएसटी व्यवस्था पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि 12 फीसदी और 28 फीसदी दरों के स्लैब को खत्म कर दिया गया है। दो नई दरों 5 फीसदी और 18 फीसदी को लेकर आम सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि इससे मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी की जरूरत के सभी सामानों को 12 और 18 से 5 पर लाया गया। 5 प्रतिशत टैक्स वाले सामानों को जीरो कर दिया गया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि क्या-क्या सामान सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है। मंत्री ने कहा कि किसानों से लेकर लेबर तक को तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में शामिल सभी सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन किया। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

क्या-क्या हुआ सस्ता

दूध, छेना पनीर, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा, को अब जीरो (0) त्रस्ज्ञ स्लैब में डाला गया है। यानी अब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

रोजमर्रा की चीजें जो सस्ती हुई – GST 5 फीसदी

हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, टॉयलेट शॉप बार, टूथब्रश, सेविंग क्रीम, बटर, घी, चीज़, डेयरी स्प्रैड मैकेज्ड़ नमकीन, भुजिया मिक्स्चर, बर्तन,

बच्चों की दूध पीने की बोतल, नैपकिन और डायपर सिलाई की मशीन और इसके पुर्जे

कार, बाइक, सीमेंट पर अब 28त्र की जगह 18त्र टैक्स लागू होगा। टीवी पर 28त्र से 18त्र त्रस्ज्ञ हुआ 33 जीवन रक्षक दवाइयां त्रस्ज्ञ से बाहर। इनमें 3 कैंसर की दवाएं भी शामिल हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस (GST 18 परसेंट से घटकर जीरो) थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डाइग्लोनस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स

40 फीसदी के स्पेशल दायरे में सुपर लग्जरी सामानों को रखा गया है। पान मसाला, सिगरेट गुटका और अन्य तंबाकू उत्पादों, बीड़ी को इस कैटेगरी में रखा गया है। इसके साथ ही फ्लेवर्ड कर्बोनेटेड पेय पदार्थों को भी इस स्लैब के तहत रखा है।

आम लोगों को ध्यान में रखकर GST में बदलाव

बुधवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होकर रात 9 बजे तक यानी 10 घंटे तक चली।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8-10 महीने से कह रहे थे कि आम लोगों को त्रस्ज्ञ से राहत दीजिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को ध्यान में रखकर त्रस्ज्ञ में बदलाव का फैसला किया गया। सीतारमण ने कहा सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का धन्यवाद। एक भी वित्त मंत्री अनुपस्थित नहीं रहे। उन्होंने बताया कि सभी ने दिन भर बातचीत की, लेकिन सभी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समय की मांग देखकर सभी ने समर्थन दिया, इसलिए सभी को धन्यवाद।

जीएसटी में बदलावों पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, वित्त मंत्रालय की सराहना की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में नई जीएसटी दरों को लेकर हुए फैसलों को लेकर वित्त मंत्रालय की सराहना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाना है, जिससे आम लोगों का जीवन आसान हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने। प्रधानमंत्री ने बताया कि इन सुधारों से किसान, एमएसएमई सेक्टर, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी लाभान्वित होंगे। छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए व्यापार करना आसान होगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य आम लोगों की जिंदगी को सरल बनाना और छोटे व्यवसायों के लिए कारोबार का माहौल बेहतर करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की थी कि जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू कर दिए जाएंगे। इससे कर का बोझ काफी कम हो जाएगा और छोटे उद्योगों को

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में एफआरए उल्लंघन पर राहुल चिंतित, जनजातीय मामलों के मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली एजेंसी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने पत्र में कहा कि इस परियोजना को लेकर जनजातीय परिषद और स्थानीय समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी विकास योजना न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सम्मान के सांविधानिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।

राहुल गांधी का आरोप- दबाव में ली गई एनओसी

राहुल गांधी ने लिखा, ग्रेट निकोबार परियोजना को मंजूरी देने में वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद ने बताया है कि निकोबारी और शोम्पेन समेत जनजातीय समुदायों से अधिनियम के तहत ठीक से सलाह-मशविरा नहीं किया गया।% उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पूरी जानकारी दिए दबाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) ली गई और बाद में जब असली जानकारी सामने आई तो परिषद ने उसे वापस ले लिया।

आदिवासी समुदाय को ये सता रहा डर

गांधी ने तीन सितंबर को लिखे अपने पत्र में

कहा कि आदिवासी समुदाय 2004 की सुनामी के दौरान विस्थापित हो गए थे और अपनी पैतृक भूमि पर वापस नहीं लौट पाए। अब उन्हें डर है कि यह परियोजना उनकी जीवनशैली और अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया कि जनजातीय परिषद और स्थानीय समुदायों की चिंताओं को गंभीरता से देखें और वन अधिकार अधिनियम का सही मायने में पालन सुनिश्चित करें।

जयराम रमेश भी परियोजना का लगातार कर रहे विरोध

कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भी इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह पारिस्थितिकी और क्षेत्र के वनवासियों और आदिवासियों के अधिकारों के लिए हानिकारक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसे जबरन आगे बढ़ा रही है।

कांग्रेस सांसद टैगोर ने भी इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को लिखा था पत्र

पिछले हफ्ते कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर निकोबारी जनजाति के सांविधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। टैगोर ने कहा था कि प्रशासन ने गलत दावा किया कि स्न्नक्र के तहत अधिकार तय हो चुके हैं और इसी आधार पर 13,075 हेक्टेयर जंगल की जमीन को परियोजना के लिए साफ कर दिया गया। लेकिन जनजातीय परिषद ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि इस प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा करवाई जाए, स्न्नक्र के अधिकार पूरी तरह मान्य किए जाएं, जब तक कानून का पालन न हो प्रोजेक्ट रोका जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।

पीएम की यूरोपीय नेताओं से फोन पर वार्ता, व्यापार से लेकर वैश्विक चुनौतियों तक कई मुद्दों पर चर्चा

नई दिल्ली एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापारिक सहयोग, हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा

सहित कई अहम वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। पीएम मोदी ने भारत-ईयू संबंधों को और मजबूत बनाने पर बल दिया, वहीं यूरोपीय नेताओं ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहराने की इच्छा जताई। बातचीत में रूस-यूक्रेन संघर्ष, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने जैसे विषय भी शामिल थे उन्होंने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र संपन्न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उनके बीच यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने दोनों नेताओं को अगले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए भारत आमंत्रित किया।

बंगाल विधानसभा, भाजपा चीफ-व्हिप को मार्शलों ने घसीटकर निकाला

5 विधायक सस्पेंड, ममता ने सदन में मोदी चोर-वोट चोर के नारे लगाए

कोलकाता एजेंसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज को बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोल रहीं थीं। तभी विपक्ष (भाजपा) ने नारेबाजी शुरू कर दी।

भाजपा विधायक 2 सितंबर को विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निलंबन का विरोध कर रहे थे। टीएमसी विधायकों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। जब विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंच गए तो स्पीकर बिमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। घोष के बाहर जाने से इनकार करने पर मार्शलों को बुलाया गया। शंकर घोष को घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया। बाहर निकालते समय वो गिरकर बेहोश हो गएए उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया।

घोष के अलावा दो अन्य भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल और मिहिर गोस्वामी को भी सदन से निलंबित कर दिया गया है। वहीं स्पीच के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने मोदी चोर और वोट चोर के नारे लगाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा का तीन दिन का विशेष सत्र 1 सितंबर को शुरू हुआ था। 3 सितंबर को करम पूजा के कारण राजकीय छुट्टी थी। आज सत्र का आखिरी दिन है।

ममता ने कहा, भाजपा बंगाल विरोधी

बंगाल भाजपा प्रवासियों पर हमलों पर विधानसभा में चर्चा के खिलाफ हैए क्योंकि ये घटनाएं भगवा पार्टी शासित राज्यों में हो रही हैं। हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हैंए लेकिन भाजपा बंगाली विरोधी है। भाजपा की तानाशाही और औपनिवेशिक मानसिकता है, वह बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है। भाजपा ने विदेशी ताकतों के सामने भारत का सम्मान बेच दिया है। केंद्र कभी अमेरिका के सामनेए तो कभी चीन के सामने भीख मांगता है।

भाजपा नेता बोले... ममता ने पूरे मोदी समुदाय को गाली दी

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने सदन में पूरे मोदी समुदाय को गाली दी है। उनके खिलाफ केस करेंगे। सुवेंदु विधानसभा के सत्र से पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। 2 सितंबर को बहस के दौरान सुवेंदु ने टीएमसी पार्टी को पाकिस्तान का एजेंट कहा था। इसके बाद उन्हें कार्यवाही बाधा डालने के आरोप में विशेष सत्र के बचे हुए एक दिन लिए सस्पेंड कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव-

भाजपा 2021 में पहली बार बंगाल में विपक्षी पार्टी बनी थी। वह 2026 में टीएमसी को कांटे की टक्कर देने की कवायद में है। हालांकि भाजपा के लिए यह सब अकेले करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा और दिल्ली की तरह आरएसएसै बंगाल में भी उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहा है।

चोरों की पार्टी है बीजेपीः ममता

पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी भ्रष्टों की पार्टी है और वोट चोरों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमने संसद में देखा कि कैसे भाजपा ने हमारे सांसदों को परेशान करने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया। सीएम ने कहा कि बंगाल में एक दिन ऐसा जरूर आएगा, जब भाजपा का एक भी विधायक बंगाल विधानसभा में नहीं बैठेगा। लोग बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। सीएम बनर्जी ने कहा कि बस कुछ दिन इंतजार कीजिए, लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार जल्द ही गिर जाएगी।

ममता ने बीजेपी को वोट चोर कहा

सीएम ने कहा कि विधानसभा में बीजेपी मुझे बोलने नहीं दे रही है, इसलिए अगली बार जब बीजेपी बोलेगी तो चोर-चोर बोलकर उन्हें भी बोलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगालियों को लेकर सदन में चर्चा करना नहीं चाहती इसलिए विधानसभा में हंगामा कर रही है। सीएम ने कहा कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया पर विधानसभा में हुए हंगामा का वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनके नेताओं ने आज सदन में लोकतंत्र की हत्या कर दी।

पुतिन बोले- ट्रम्प भारत-चीन को धमकाना बंद करें - दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन से सीधा संदेश दिया है। बुधवार को चीन में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने एक बार फिर बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की मांग दोहराई। चीन की चार दिन की यात्रा पूरी करने के बाद पुतिन ने कहा कि भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते वजन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि दुनिया की राजनीति या सुरक्षा पर किसी एक देश का दबदबा न रहे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन जैसे आर्थिक दिग्गज मौजूद हैं, हमारी अर्थव्यवस्था भी क्रय शक्ति समानता के हिसाब से टॉप-4 में है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक देश राजनीति या सुरक्षा में हावी हो। सब बराबर होने चाहिए। उन्होंने एकध्रुवीय दुनिया यानी यूनिपोलर वर्ल्ड के मॉडल को पुराना और नाइंसाफी करार दिया। तो आखिर यह बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? और पुतिन जिन देशों की बात कर रहे हैं, वे कौन-कौन से हैं?

पुतिन का इशारा किस तरफ

पुतिन ने साफ किया कि नई बहुध्रुवीय दुनिया पुराने साम्राज्यवादी ढाँचे की नकल नहीं करेगी और न ही कोई नया दबंग ताकत पैदा होगा। उन्होंने क्र्रद्धष्टस् और स्ष्ह्र जैसे मंचों को इसका उदाहरण बताते हुए कहा कि यहाँ सभी देश बराबरी से भागीदारी करते हैं।

दरअसल, शीत युद्ध के बाद से वैश्विक राजनीति में अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत बना रहा। इस दौर को unipolar world ऑर्डर कहा गया, जहाँ एक ही सुपरपावर का दबदबा था।

मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या है

लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन, भारत, रूस और ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ न सिर्फ तेजी से बढ़ रही हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज भी बुलंद कर रही हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि वैश्विक फैसले सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि कई मजबूत देशों और समूहों की ओर से मिलकर तय किए जाएँ। क्र्रद्धष्टस् और स्ष्ह्र जैसी ग्रुपिंग्स इसी सोच की झलक हैं, जहाँ सदस्य देश बराबरी से भागीदारी की बात करते हैं। आसान भाषा में समझें तो बहुध्रुविय दुनिया का मतलब है एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जहां कोई अकेला बॉस न हो बल्कि कई देशों की ताकत और हित एक साथ मिलकर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा का संतुलन तय करें। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति का मकसद आर्थिक संरक्षणवाद और सैन्य ताकत से फिर से अमेरिका की बादशाहत कायम करना है जिसे पुतिन ने चुनौती दी है। भारत- सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का संबंध पश्चिम और रूस, चीन के साथ भी हैं। चीन- अमेरिका को टक्कर देने वाली इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पावर। ट्रंप ने टैरिफ लगाकर चीन को झुकाना चाहा मगर ऐसा हुआ नहीं।रूस- सैन्य ताकत और ऊर्जा संसाधनों के जरिए अहम भूमिका निभाता है। ब्राजील-लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, BRICS का अहम हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका-अफ्रीका में राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व का दावा करता है। कुछ बड़े समूह भी है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे BRICS (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका), SCO- शंघाई सहयोग संगठन (चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान + मध्य एशियाई देश)। तीसरा त्र20, भले ही ये एक ग्लोबल मंच है, लेकिन इसमें उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अमेरिकी यूरोपीय दबदबे को संतुलित करती हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ईरान जैसे देश भी अक्सर मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थन करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि सिर्फ अमेरिका या पश्चिम ही नियम तय करें।

स्वच्छता से खुलता है समृद्धि का द्वार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

स्वच्छता हमारी आदत, परंपरा, दिनचर्या और संस्कारों में सदियों से है शामिल

भोपाल एजेंसी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वच्छता से समृद्धि आती है। स्वच्छता हमारी परंपरा, दिनचर्या और संस्कारों में सदियों से शामिल रही है, किंतु समय के साथ हम इसे भूलते गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन आदतों और संस्कारों को पुनर्जीवित कर स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को इंदौर में ÷स्वच्छता ही सेवा÷ अभियान के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता कर्मवीरों के सम्मान और सहभोज कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने लगातार आठ बार प्रथम स्थान प्राप्त कर देश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए इंदौर के सभी 36 लाख नागरिक और विशेष रूप से स्वच्छता कर्मवीर बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में विश्वस्तरीय पहचान बनाई है। यह उपलब्धि टीम भावना, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सफाईकर्मियों की अथक मेहनत से संभव हुई है।

इस अवसर पर महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री रमेश मेंदोला, श्री गोलू शुक्ला, श्रीमती मालिनी गौड, श्री महेंद्र हार्डिया, विधायक श्री मधु वर्मा एवं सुश्री ऊषा ठाकुर, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष श्री सावन सोनकर, सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष श्री प्रताप करोसिया, श्री सुमित मिश्रा, श्री श्रवण चावड़ा, पूर्व विधायक श्री जीतू जिराती, पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वच्छता कर्मवीरों का सम्मान कर उनके साथ भोजन किया। उन्होंने इंदौर को स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार आठ बार अव्वल बनाने के लिए स्वच्छता कर्मवीरों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मवीरों ने अपनी कर्मठता, लगन, मेहनत, सेवा और समर्पण भाव से कार्य कर इंदौर को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाया है। साथ ही स्वच्छता कर्मवीर सही अर्थों में सम्मान के हकदार है। उन्होंने ÷स्वच्छता का महागुरु÷ लोगो का विमोचन भी किया। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पार्षदों को भी पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश के पहले जीरो वेस्ट जू (प्राणी संग्रहालय) का शुभारंभ भी किया।

इलेक्ट्रिक एसी बस में किया सफर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर की लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत की 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया। इंदौर को कुल 150 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी, इनमें से उक्त 50 बसों का लोकार्पण किया गया है। इन बसों में डिजिटल पेमेंट व्यवस्था भी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डिजिटल पेमेंट व्यवस्था का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बस में सवार भी हुए और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जीपीएस, सीसीटीवी, पेनिक बटन एवं अन्य सुविधाओं को

देखा। उन्होंने कहा कि इंदौर में सड़क, वायु मार्ग और रेल मार्ग का तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे इंदौर से देश में चारों ओर कनेक्टिविटी बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर के प्रसिद्ध श्री रणजीत हनुमान मंदिर के पुनर्विकास कार्यों का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वर्चुअली भूमिपूजन किया। उन्होंने कहा कि रणजीत हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से हमें हर क्षेत्र में रण जीतने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर मंदिर के विकास के संबंध में तैयार प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। इस मंदिर के पुनर्विकास पर 7 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। भक्तों के लिए अनेक सुविधाएं जुटाई जाएंगी। इस राशि से भव्य द्वार शेड एवं बाउंड्रीवॉल पाथ-वे और उद्यान विकसित करने के कार्य किए जाएंगे। मंदिर के वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखा जाएगा। यह कार्य मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर ने विश्व मानचित्र पर अपना नया स्थान बनाया है। इंदौर स्वच्छता में लगातार आठ बार से अव्वल है। इंदौर में लोक परिवहन को नई दिशा मिली है, अब यह डिजिटल इंदौर की ओर बढ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्पों को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में तेजी से पूरा किया जा रहा है।महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंदौर का विकास आगामी वर्ष-2050 को दृष्टिगत रखते हुए तेजी से किया जा रहा है। इंदौर का चहुँमुखी विकास हो रहा है। यहां स्वच्छता के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इंदौर नगर निगम डिजिटल क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे हैं नवाचारों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में विधायकगण नगर निगम के सभापति, महापौर परिषद सदस्य, पार्षदगण तथा बड़ी संख्या में सफाई मित्र और उनसे जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य नागरिकगण उपस्थित थे।

महिला स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण हेतु विशेष जागरूकता अभियान प्रारंभ

जिला ब्यूरो- कैलाश लाहोरी

सिवनी / प्रशासक वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास सुश्री ईशा बाल्मिक द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार जिले में 02 सितंबर से 12 सितंबर 2025 तक महिला केंद्रित विषयों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, शिविर, संवाद एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बतया कि अभियान के अंतर्गत 10 दिवसीय विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार 03 सितंबर को नर्सिंग कॉलेज जिला अस्पताल सिवनी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉ.मनीषा सिरसाम एवं सहयोगी श्री संदीप सोनकेसरिया ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम की जानकारी साझा की। डॉ. सिरसाम द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना एवं देश में घटते लिंगानुपात को सुधारना है। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को दण्ड, कारावास एवं जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्री संदीप सोनकेसरिया द्वारा सोनोग्राफी तकनीक के संबंध में उपस्थित कार्यकर्ताओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में कार्यालय वन स्टॉप सेंटर सिवनी से सेंट्रल एडमिस्ट्रेटर श्रीमती नारायणी सक्सेना, केसवर्कर श्रीमती सोनल सक्सेना, श्रीमती वर्षा बैस एवं सुरक्षाकर्मी दीपक रजक उपस्थित रहे।

अकैडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के अंबुज सर को मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025

उद्घोष समय सतना, अंकित शर्मा

सतना- अकैडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल के गणमान्य शिक्षक अंबुज सर को इस वर्ष ए एच पी एस मुख्यालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025% से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी शिक्षा के प्रति अटूट समर्पण, मेहनत और नवाचार को मान्यता देने के लिए दिया गया है। इस विशेष पुरस्कार से उन्हे विद्यालय में प्राचार्य महोदया द्वारा विशेष तौर से स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित किया गया। देशभर में अकैडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल की 120+ शाखाओं में से सतना की शाखा ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। स्कूल की सभी शाखाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी-अपनी शिक्षा तकनीक, उपलब्धियों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर आधारित प्रेजेंटेशन दिल्ली मुख्यालय में प्रस्तुत की थी। अनगिनत प्रविष्टियों में से सतना की प्रस्तुति को विशेष रूप से सराहना मिली और अंबुज सर इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के विजेता बने। इस उपलब्धि पर स्कूल के चेयरमैन श्री शम्मी पुरी, डायरेक्टर ष्ट सनातन अग्रवाल, प्राचार्या डॉ. हिमानी सिंह और उप प्राचार्य श्री संजीव सिंह सेंगर ने उन्हें बधाई दी और उनके योगदान की सराहना की।

धर्म नहीं अब धंधा होगा गरीब की पीठ पर डंडा होगा

उद्घोष समय सतना, अंकित शर्मा

यह अपना सतना है

इसकी बसाहट का आंशिक इतिहास यह है कि जब देश में अंग्रेजी सरकार थी और उसने यहां रेलवे रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया उसके बाद ही इस शहर को एक नाम मिला ÷सुतना÷। शहर के मध्य रेलवे स्टेशन के समीप स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन में एक पत्थर लगा था जिसमें ÷सुतना÷ लिखा था। उक्त विद्यालय के भवन का नवनिर्माण होने पर वह पत्थर कुछ वर्षों पूर्व ही हटा दिया गया लेकिन उस पत्थर को हटाने के 5- 6 दशक पहले ही सुतना सतना हो चुका था। रेल लाइन बिछाने के काम के साथ ही जब सतना में आबादी का विकास शुरू हुआ तो यहां ऐसे लोग भी आकर बसे जो मानवता के पुजारी थे उन्होंने मानव हित के लिए तालाब और कुआं खुदवाए उन तालाब और कुओं का लोग निशुल्क उपयोग करते थे। धर्मशालाएं बनवाई जहां कोई भी व्यक्ति दो-तीन दिन ठहर सकता था किंतु रूपयो के हबसी आज के धननासेठो ने अपने पुरखों की भावनाओं की हत्या करते हुए तालाब कुआं धर्मशाला सबका नामोनिशान खत्म कर दिया। धर्मशाला बनवाने के लिए जमीन मुफ्त में मिलती थी। उसी मुफ्त की जमीन पर पुरखों के द्वारा निर्मित की गई धर्मशालाओं की जमीन पर वर्तमान में लॉज का निर्माण हो गया

धर्मशालाओं की कब्र पर बने शहर के इन लाजो में अब कोई गरीब सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। सरकार का ध्यान भी इस तरफ नहीं है क्योंकि यह काम सब उन्हीं लोगों ने किया जिनकी तिजोरी महात्मा गांधी के फोटो छपे कागजों की गडिडयों से भरे पड़े हैं। कोई गरीब फल या सब्जी का ठेला सड़क किनारे लगा ले तो नगर निगम सरकार के आदेश पर बहादुर नौजवान अतिक्रमण विभाग के पहलवान तराजू , बांट ठेला जप्त करते हुए सामान सड़क पर बिखेर देंगे और ठेला कि वह दुर्गत करते हैं कि उसको बनवाने में गरीब को हजारों रुपया खर्च करना पड़ेगा। जुर्माना देगा तब तराजू बांट वापस मिलेगा लेकिन पूरे शहर में अधिकांश दुकानदार दुकान के आगे सड़क पर दस- दस अतिक्रमण किए हुए हैं। हर मिनट यातायात जाम होता है परंतु मजाल है कि नगर निगम का अतिक्रमण विभाग उस तरफ नजर उठा कर देख ले। सरकारी जमीनों को रईसजादो से मुक्त कराने की बजाय सरकार ने रैन बसेरा की शुरुआत की है लेकिन वह ऐसी जगह संचालित हैं जहां हर कोई पहुंच ही नहीं पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि आज धर्म को जमीदोज करके जो लोग धंधा चला रहे हैं सत्ता भी उन्हीं का साथ देती है। राजनीतिक पार्टियों में बड़े पद पर वही लोग आसीन किए जाते हैं। गरीब जो किसी प्रकार सड़क पर रोजी-रोटी कमाकर परिवार पाल रहा है उसे हर समय नगर निगम के कर्मचारी या पुलिस जवान के डंडों और मां बहन की गलियों का सामना करना पड़ता है।

भीमगढ़ बाँध के खोले गए चार गेट छोड़ा जा रहा 21 हजार 500 घन फीट प्रति सेकेंड पानी

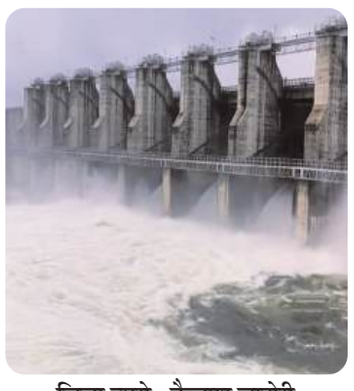

जिला ब्यूरो- कैलाश लाहोरी

सिवनी / संजय सरोवर परियोजना अंतर्गत भीमगढ़ बाँध का जलस्तर 518.90 मीटर तक पहुँचने पर अतिरिक्त जल छोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, तिलवारा बाँयी तट नहर संभाग केवलारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 03 सितम्बर 2025 को सुबह 9 बजे से बाँध के गेट क्रमांक 4, 5, 6 एवं 7 को 1-1 मीटर तक खोला खोला गया है। चारों गेट से 21,000 घनफीट प्रति सेकेंड (595 क्यूमेक्स) तथा पॉवर हाउस से 500 घन फीट प्रति सेकेंड की दर से पानी बैनगंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने बैनगंगा नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।

नरवर के मगरौनी मैं मनाई गई फूल डोल ग्यारस निकाले 14 विमान दर्शन करने पहुंचे हजारों दर्शक मगरौनी सजा वृंदावन जैसा

खबर दिनांक 4 सितंबर को साम 5 बजकर 30 मिनट की जहां मगरोनी मैं आज फूल डोल ग्यारस निकाले गए 14 विमान जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालूओं पहुंचे दर्शन करने मगरौनी दर्शकों ने बताया कि मगरौनी आज कोई वृंदावन से कम नहीं सजा आज मगरौनी के पूरे बाजार में वृंदावन जैसी गलियां सजी हुई हैं वहीं क्षेत्रीय विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने बताया कि आज हमारे मगरौनी मैं हजारों श्रद्धालु फूल डोल ग्यारस के विमानों के दर्शन आते हैं और क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि यह सेकडो सालों हमारे यहां विमान निकलते आ रहा है यह हमको भी पता नहीं की हमारे पुरखो के समय से और पहले से विमान निकलते आ रही है और आज का दिन हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है आज के दिन हमारे यहां सभी क्षेत्र वासी उपवास रखते हैं और आगे सुनिए क्षेत्रीय विधायक रमेश प्रसाद खटीक ने क्या कहा

आस्ता बाल विकास परियोजना कार्यालय में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा

सूचना के कुछ घंटे में पुलिस ने पकड़ा आरोपी, चार मोबाइल बरामद

संवाददाता प्रेम सिंह राजपूत, स्टेट ब्यूरो, उद्घोष समय, जशपुर

जशपुर। आस्ता स्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना मनोरा-2 के कार्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के महज कुछ घंटों के भीतर ही जशपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से चार नग मोबाइल फोन बरामद कर लिए।

प्रकरण के अनुसार, 02 सितंबर को परियोजना अधिकारी अंदरमाला बखला ने थाना आस्ता में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 01 सितंबर की शाम कार्यालय बंद करने के बाद 02 सितंबर की सुबह कार्यालय खोलने पर ताला टूटा पाया गया। जांच करने पर चार सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन, प्रत्येक की

कीमत 10,499 रुपए, कुल 41,966 रुपए मूल्य के मोबाइल चोरी होना पाया गया। तत्काल पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।

जांच के दौरान पुलिस ने आस-पास की दुकानों और घरों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में संदिग्ध युवक नज़र आया, जिसे स्थानीय लोगों ने पहचानकर उसका नाम सुब्रत सोनवानी उर्फ पप्पू, उम्र 19 वर्ष, निवासी कुम्हारपारा कुसमी बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन पर पुलिस टीम कुसमी रवाना हुई और बाबा चौक में आरोपी को पकड़ लिया। उसकी तलाशी में चोरी किए गए चारों मोबाइल फोन बरामद हुए जिन्हें वह बेचने की फिराक में था।

आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ थाना आस्ता में बीएनएस की धारा 331(4) एवं 305(द्द) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया और आरोपी को चोरी किए गए मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक दीपक बड़ा, प्रधान आरक्षक संदीप एक्का, आरक्षक सुरेश गौड़ और अनिल भगत की अहम भूमिका रही। पुलिस ने जब्त किए गए मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आगे की जांच जारी है।

बरगवां अमलाई में भाजपा पार्षद समाजसेवी पवन चीनी का अनुकरणीय प्रयास : स्वच्छता की नई मिसाल, अपना पैसा लगाकर करा रहे वार्डों की साफ- सफाई, वार्ड का विकास पहली प्राथमिकता- पवन चीनी

अनूपपुर द्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के लिए प्रदेश सरकार करोड़ों पए खर्च कर रही है, लेकिन अनूपपुर जिले की नगर परिषद बरगवां अमलाई में भाजपा पार्षद पवन चीनी ने जो कदम उठाया है, उसने सरकारी प्रयासों को आइना दिखा दिया है। अपने निजी खर्च पर मजदूर लगाकर सफाई अभियान चलाने वाले पवन चीनी ने न केवल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि एक अनुकरणीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।अनूपपुर और शहडोल की सीमा पर स्थित नगर परिषद बरगवां अमलाई के वार्ड नंबर 7 से भाजपा पार्षद पवन चीनी इन दिनों इलाके में चर्चा का विषय बने हुए है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 को लेकर जहां प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर राशि खर्च कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर इसके अपेक्षित नतीजे नहीं दिख रहे। इस बीच पवन चीनी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद सफाई का बीड़ा उठाया है। बीते कई दिनों से पवन चीनी ने अपने निजी खर्च पर दो दर्जन से अधिक महिला और पुरुष मजदूरों को क्षेत्र में लगाया है। इनमें रेलवे स्टेशन के पास स्थित कालोनियां, बसंतपुर दफाई, मैगजीन दफाई, अमलाई स्टेडियम कॉलोनी, धोबी दफाई, नवीन नगर, अतिरिक्त भवन के पास और अमलाई दुर्गा मंदिर बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान शामिल है। यहां मजदूर कचरा उठाने, गाजर घास की सफाई करने और गलियों को व्यवस्थित करने का कार्य कर रहे है। खास बात यह है कि पवन चीनी खुद भी सफाई में हाथ बंटाते हुए मजदूरों के साथ पसीना बहा रहे हैं। उनका यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के आह्वान को सार्थक करने वाला है। स्थानीय लोग भी इस पहल से प्रभावित नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके सफाई अभियान के वीडियो और तस्वीरें जमकर वायरल हो रहे है। नागरिकों का कहना है कि जब परिषद का भारी-भरकम बजट सफाई पर खर्च नहीं हो रहा तो एक पार्षद का यह प्रयास वास्तव में प्रेरणादायक है। स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। मैने सोचा कि अगर हम सब मिलकर आगे आएं तो अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बना सकते है। मैंने मजदूरों के साथ खुद सफाई करने का निर्णय इसलिए लिया ताकि समाज को संदेश दिया जा सके द्य स्थानीय नागरिकों के बयान

अमलाई नगर वासियों ने बतलाया कि हमारे क्षेत्र में पहले सफाई की गंभीर समस्या थी, लेकिन पवन चीनी के प्रयासों से हालात तेजी से बदल रहे है। यह अनुकरणीय पहल है, जिससे लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है। सनी गुप्ता निवासी दुर्गा मंदिर बाजार नगर परिषद की सफाई व्यवस्था कागजों तक ही सीमित रही है। पहली बार हमने देखा कि एक पार्षद अपने पैसे से मजदूर लगाकर सफाई करवा रहे है और खुद भी काम कर रहे है। यह काबिल-ए-तारीफ है। रवि दुबे निवासी अमलाई स्टेडियम के पास का कहना है कि बरगवां अमलाई के पार्षद पवन चीनी का यह प्रयास न केवल स्थानीय निकाय की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि समाज को एक नया रास्ता भी दिखाता है। उनका सफाई अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छता का संदेश है और यह बताता है कि जज्बा हो तो बदलाव किसी भी स्तर पर संभव है।

जशपुर पुलिस का ऑपरेशन शंखनाद, छह गौवंश तस्करों से मुक्त

एक आरोपी गिरफ्तार, 1250 से अधिक गौवंशों को अब तक छुड़ाया गया

संवाददाता - प्रेम सिंह राजपूत, स्टेट ब्यूरो, उद्घोष समय, जशपुर

जशपुर,। जशपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए छह नग गौवंशों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा लिया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। मामला चौकी मनोरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम हाड़िकोना, नगरकोना का है।

पुलिस के अनुसार 02 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से गौवंशों को बेरहमी से मारते-पीटते हुए झारखंड की ओर ले जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस टीम ने ग्राम कोल्हू डीपा के जंगल में घेराबंदी कर छापा मारा और मौके पर एक व्यक्ति को छह गौवंशों के साथ पकड़ लिया। आरोपी ने अपना नाम अनिल एक्का, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम धनीटोली, थाना आस्ता बताया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह

गौवंश गोविंदपुर, झारखंड निवासी हासमीन नामक व्यक्ति के कहने पर वहां ले जा रहा था। जब उससे पशुओं के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सभी छह गौवंशों को सकुशल बरामद कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी की निशानदेही पर एक अन्य तस्कर की पहचान भी की गई है जिसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी।

आरोपी अनिल एक्का के खिलाफ चौकी मनोरा में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(क)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत लगातार कार्रवाई करते हुए अब तक 1250 से अधिक गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है और 140 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से गौ तस्करों पर नकेल कस रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश पुरैना, सहायक उप निरीक्षक बालकृष्णा भगत, आरक्षक जगजीवन यादव, रविंद्र सिंह पैंकरा और भीखराम राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बरामद गौवंशों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।

कार्यक्रमों की पूर्व सूचना दें, तभी संभव होगी सुरक्षा व्यवस्था : एसपी शशि मोहन सिंह

गणेश विसर्जन जुलूस की जानकारी न मिलने से हुई अफरातफरी, प्रशासन ने जताया दुख

संवाददाता - प्रेम सिंह राजपूत, स्टेट ब्यूरो, उद्घोष समय, जशपुर

जशपुर, 05 सितंबर 2025। जिले में हाल ही में हुए गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से विशेष अपील की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने कहा है कि किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक, राजनीतिक या सामाजिक धरना, प्रदर्शन, रैली अथवा कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उसकी पूर्व सूचना प्रशासन को अनिवार्य रूप से दी जाए, ताकि आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की जा सके और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो।

पुलिस प्रशासन ने बताया कि कल की घटना का एक मुख्य कारण यह रहा कि गणेश विसर्जन जुलूस एवं डीजे कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस को पूर्व में उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस कारण पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई और अफरातफरी की स्थिति में कई लोग घायल हो गए तथा जनहानि भी हुई। प्रशासन और पुलिस ने इस दुखद घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया है।

एसपी शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट किया कि पूर्व सूचना मिलने पर पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा इंतजाम सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। नागरिकों से अपेक्षा है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से पूर्व प्रशासन को सूचना दें, ताकि पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। सभी से आग्रह है कि प्रशासन का सहयोग करें और मिलकर जिले में शांति एवं सौहार्द बनाए रखें।

*जिले में 01 जून से अब तक 8712.8 मिमी वर्षा

उद्घोष न्यूज़ जिला संवाददाता नारायण प्रधान

जशपुरनगर। जशपुर जिले में 01 जून से अब तक 9130.3 मिमी वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 04 सितम्बर तक की स्थिति में 8654.6 मिमी औसत वर्षा हुई है। बीते दिवस जिले में 205.4 मिमी वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसील जशपुर में 1074.3 मिमी, मनोरा में 1098.9 मिमी, कुनकुरी में 1268.0 मिमी, दुलदुला में 574.9 मिमी, फरसाबहार में 730.7 मिमी, बगीचा में 985.5 मिमी, कांसाबेल में 844.3 मिमी, पत्थलगांव में 851.3 मिमी, सन्ना में 1045.8 मिमी एवं बागबहार में 656.6 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा कुनकुरी में दर्ज की गई है।

अब जान जोखिम में डाल कर नहीं करना पड़ेगा नदी पार

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जिले में चार उच्च स्तरीय पुल निर्माण को दी मंजूरी,विकास की सौगातों से बदल रही है जशपुर की तस्वीर*

उद्घोष न्यूज़ जिला संवाददाता नारायण प्रधान

जशपुरनगर। जिलेवासियों के लिए आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सड़क और पुल-पुलिया का तेजी से विकास कर रहे हैं। जिले में पुल-पुलिया की कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय ने चार वृहद पुल निर्माण के लिए 13 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। इनमें गुलझरिया बम्हनी मार्ग पर श्री नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण शामिल है। पुलविहिन इस नदी पर पुल निर्माण करने का मांग ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से किया जा रहा था। बरसात के दिनों में इस नदी को पार करने में ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने श्री नदी पर पुल निर्माण के लिए 3 करोड़ 66 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस पुल के निर्माण से गुलझरिया से बम्हनी के बीच बसे लगभग दर्जन भर गांव के रहवासियों का विकासखंड मुख्यालय दुलदुला तक पहुंच आसान हो जाएगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। इसके अलावा सीएम श्री साय ने जिले में 1.71 करोड़ की लागत से बेनसारी नाला में किलकिला से केराकछार रोड में पुल पुलिया का निर्माण,मैनी नदी में कांसाबेल से शब्दमुंडा मार्ग में जर्जर पुलिया के जगह नए पुल निर्माण के 3.49 करोड़ की लागत से निर्माण किया जा रहा है और जिला मुख्यालय जशपुर में बांकी नदी पर जर्जर पुल हो चुके पुल की जगह नए उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए 4 करोड़ 60 लाख की स्वीकृति दी है।

'जिले में विकसीत हो रहा है बुनियादी ढांचा '

किसी भी जिले के लिए विकास का पैमाना बुनियादी ढांचा को माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के गृह जिले में बीते दो साल के अंदर इस क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। सड़क व पुल के साथ ही शिक्षा,स्वास्थ्य,पानी की सुविधा विकसीत कर,आम नागरिकों का जीवन सुखद बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार जशपुर जिले के लिए दिल खोल कर बजट दे रही है। सरकार का लक्ष्य जशपुर को विकसित जिला के रूप में स्थापित करना है।

प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन हेतु 04 लाख की राशि स्वीकृत

उदोष न्यूज़ जिला संवाददाता नारायण प्रधान

जशपुरनगर। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन को आर.बी.सी. 6-4 के तहत् 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत दी है। फरसाबहार तहसील अंतर्गत ग्राम बिरही पानी, निवासी स्व. रंजीत टोप्पो का तालाब के पानी में डूबने से 13 अक्टूबर 2024 को मृत्यु हो गई। मृतक के निकटतम वारिस उनके पत्नी फेदरिका टोप्पो हेतु 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घोलेंग में अतिथि शिक्षक के विभिन्न पदों पर नियुक्त हेतु दावा-आपत्ति 11 सितम्बर तक

उद्घोष न्यूज़ जिला संवाददाता नारायण प्रधान

जशपुरनगर। जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के द्वारा शिक्षण सत्र 2025-26 हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए मेरिट आधारित भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया था एवं विज्ञप्ति 28 जुलाई .2025 के द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घोलेंग में प्राप्त आवेदन पत्रों का विषयवार पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। विद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थियों को पात्र व अपात्र की सूची में आपत्ति होने पर अपना लिखित अभ्यावेदन 11 सितम्बर 2025 तक आमंत्रित किया गया है। अभ्यावेदन संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घोलेंग में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

*नव संकल्प शिक्षण संस्थानः छ. ग. लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा तैयारी हेतु नया बैच का प्रारंभ 8 सितम्बर से

जशपुरनगर। नव संकल्प शिक्षण संस्थान जशपुर में छ. ग. लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए नया बैच 8 सितम्बर से प्रारंभ हो रहा है द्य इस बैच में आगामी छ.ग. पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करायी जायेगी, इस बैच की समयावधि 5 महीने की होगी, प्रतिदिन सुबह 9रू00 बजे से 1 बजे तक 3 कक्षाएं संचालित होंगी, हर शनिवार को साप्ताहिक टेस्ट भी आयोजित किये जायेंगे। यह बैच पूर्णतः डे स्कॉलर बैच होगी, इस बैच में कुल 40 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, ऐसे सभी छात्र जो आगामी छग पीएससी प्री 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो कार्यालयीन समय पर नव संकल्प में उपस्थित होकर प्रवेश ले सकते हैं

ग्राम पंचायत जामबहार में महाघोटाला, ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर

कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से होगी शिकायत, आंदोलन की चेतावनी

संवाददाता - प्रेम सिंह राजपूत, स्टेट ब्यूरो, उद्घोष समय, रायगढ़, 05 सितंबर 2025। ग्राम पंचायत जामबहार में हुए कथित महाघोटाले ने ग्रामीणों के बीच गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। पंचायत सचिव प्रताप कुमार चौहान की लापरवाही और संदिग्ध कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, जिससे ग्रामवासियों का विश्वास टूट गया है।

ग्रामीणों के अनुसार पंचायत के फंड का दुरुपयोग करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुँच सका। कई निर्माण और विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, जबकि खर्च का हिसाब कागज़ों पर पूरा दिखाया गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सचिव ने मिलकर भ्रष्टाचार की गतिविधियों को अंजाम दिया है। इस मामले में ग्रामीण अब संगठित होकर कलेक्टर रायगढ़ और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत करने की तैयारी में हैं। उनका कहना है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिला स्तर की जांच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी। वे दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घोटाले ने पंचायत के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच में देरी हुई तो ग्रामीण और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इस पूरे प्रकरण पर जिले भर की निगाहें टिकी हुई हैं। जामबहार में हुए इस महाघोटाले का पर्दाफाश कब होगा और दोषियों को कब सजा मिलेगी, यह देखने वाली बात होगी। ग्रामीणों का मानना है कि सच सामने आकर रहेगा और दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

प्राकृतिक खेती भविष्य की कृषि है आने वाला समय प्राकृतिक कृषि का ही है - डॉ शेखर सिंह बघेल

कृषि प्रसार अधिकारियों का रबी फसल पूर्व प्रशिक्षण संपन्न

सिवनी जिला ब्यूरो- कैलाश लाहोरी

सिवनी/ कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के दर्पण सभागार में आज रबी पूर्व अतः सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया प्रशिक्षण में कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सिवनी उपसंचालक कृषि श्री सुधीर कुमार धुर्वे, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ शेखर सिंह बघेल, सहायक संचालक कृषि अभियांत्रिकी शायला नाज कुरैशी एवं समस्त सहायक संचालक कृषि, कृषि अधिकारी एवं विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे प्रशिक्षण में कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉ शेखर सिंह

बघेल ने बताया कि आगामी समय में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन योजना का व्यापक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करने की अति आवश्यकता है, इसके अंतर्गत किसानों की लागत कम करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, किसानो की आय बढ़ाना एवं सुरक्षित जहर मुक्त भोजन सुनिश्चित करना मुख्य लक्ष्य है।

साथ ही आगामी रबी फसल के बुवाई के पूर्व महत्वपूर्ण कृषि संबंधित कार्यो पर ध्यान केंद्रित कर बेहतर खेती करने हेतु जानकारी दी ड्रोन तकनीकी द्वारा छिड़काव, फसल विविधीकरण के अंतर्गत कुसुम, सूरजमुखी , कपास अरहर, मूंग, उड़द की खेती नैनो उर्वरकों का सही समय पर उपयोग एवं बेहतर लाभ कैसे लें, फसल अवशेष प्रबंधन , अपनी क्यारी - अपनी साग, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके अलावा विकसित कृषि संकल्प अभियान (रबी) 2025 हेतु विस्तार से बताया गया, इस दौरान डॉ निखिल सिंह वैज्ञानिक ने सिवनी जिले रबी की प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चना की प्रमुख किस्म उन्नत कृषि तकनीक एवं विभिन्न प्राकृतिक खेती के उत्पाद तैयार करने के विषय में विस्तार से प्रशिक्षण प्रदान किया, इस दौरान डॉ के. के. देशमुख वैज्ञानिक, डॉ जी. के. राणा आदि की उपस्थिति रही एवं जानकारी प्रदान किया ।

बस्तर में कलेक्टर की सख्ती : 10 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

जल जीवन मिशन की लापरवाही पर गिरी गाज, अमानत राशि भी राजसात

संवाददाता - प्रेम सिंह राजपूत, स्टेट ब्यूरो, उद्घोष समय

बस्तर। 05 सितंबर 2025 । जिले में जल जीवन मिशन की रफ्तार थमने और ग्रामीणों को नल से जल न मिलने पर आखिरकार जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर हरिस एस., जो जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने 2 सितंबर को हुई समीक्षा बैठक में 10 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया।

ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों की सूची

1. यादव कन्स्ट्रक्शन, जगदलपुर
2. गणपति सेल्स, जगदलपुर
3. डीआर कन्स्ट्रक्शन, जगदलपुर
4. बीआर इन्वायरा सॉल्यूशन, भिलाई
5. बंशीलाल गंजीर, भानपुरी
6. आरबी ड्रिलर्स, केशकाल
7. छत्रपति कन्स्ट्रक्शन, जगदलपुर
8. भारत इंफ्रा, केशकाल
9. किसान बोरवेल्स, केशकाल
10. लखन सिंह, रायपुर

कलेक्टर ने इन ठेकेदारों की अमानत राशि भी राजसात कर ली, ताकि आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके।

क्यों हुई कार्रवाई?

समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि कई ठेकेदारों ने काम शुरू ही नहीं किया और जिन्होंने शुरू किया भी, वे अधर में छोड़कर चलते बने। परिणामस्वरूप 16 गांवों की पेयजल योजनाएं अधर में लटक गई और ग्रामीण बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते रहे।

कलेक्टर का अल्टीमेटम

कलेक्टर हरिस एस. ने साफ कहा ङ्क ÷जल जीवन मिशन मिशन-मोड पर चल रहा है, यहां ढिलाई का कोई सवाल नहीं। ठेकेदारों की लापरवाही सीधे जनता के जीवन से खिलवाड़

है। अब सहनशीलता की सीमा खत्म हो चुकी है।

उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अगर किसी ठेकेदार या एजेंसी ने लापरवाही दिखाई तो भारी जुर्माना वसूला जाएगा और उन्हें सरकारी प्रोजेक्ट्स से स्थायी रूप से बाहर कर दिया जाएगा।

क्यों अहम है जल जीवन मिशन?

2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना लक्ष्य।

बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित और आदिवासी इलाकों में स्वच्छ पेयजल की भारी कमी।

महिलाओं और ग्रामीणों को अब भी मीलों दूर से पानी ढोना पड़ता है।

अब होगी सख्त मॉनिटरिंग

हर महीने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग रिपोर्ट अनिवार्य।

जियो-टैगिंग और फोटोग्राफी से काम में पारदर्शिता।

तकनीकी अड़चनों का त्वरित समाधान।

अधिकारियों की नियमित फील्ड विजिट।

जिले में हड़कंप

कलेक्टर की इस कार्रवाई से जिलेभर के ठेकेदारों और एजेंसियों में खलबली मच गई है। संदेश साफ है कि जल जीवन मिशन की राह में रुकावट पैदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि पानी की किल्लत सीधे उनके जीवन-मरण का सवाल है।

मंडला लौट रहे युवकों की कार मील के पत्थर से टकराई

एक की मौत, तीन गंभीर

जबलपुर/मंडला/ प्रतिनिधि। एमपी के जबलपुर से खरीददारी कर मंडला लौट रहे युवकों की कार निवास के पास मील के पत्थर से टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं कार सवार एक युवक जितेन्द्र कुमार बर्मन की मौके पर मौत हो गई। वहीं तीन युवक गंभीर रुप से घायल हो गए, जिन्हे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस के अनुसार निवास जिला मंडला में रहने वाला जितेन्द्र बर्मन अपने तीन साथियों के साथ जबलपुर से खरीददारी करके कार से निवास के लिए रवाना हुआ। रात होने के कारण चारों दोस्तों ने मंडला रोड पर स्थित ढाबा पर ही खाना खाने का विचार बनाया। देर रात जब वे ढाबा जा रहे थे। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे मील के

पत्थर से टकराकर हवा में उछल गई। जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में जितेन्द्र बर्मन के शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं अन्य तीन युवकों को गंभीर चोटें आई। सभी लोग कार के अंदर ही फंसे रहे। देर रात रास्ते से गुजर रहे लोगों ने देखा तो पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार को सीधा किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद जितेंद्र को निकाला, वहीं घायलों को भी निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में तीनों की हालत गंभीर बनी हुई थी।

जेल प्रहरी के जन्मदिन पर बंदी ने दी पार्टी, रेस्टारेंट में देर रात तक झलके जाम

जेल अधिकारी कर्मचारी हुए शामिल

जबलपुर/ प्रतिनिधि। नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय कारागार में जेल प्रहरियों और कैदियों के बीच याराना किसी से छुपा नहीं हैं। रह-रहकर कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें जेल से बाहर निकलने पर कैदियों ने जेल प्रहरियों की आर्थिक मदद की है। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसमें जेल से बाहर निकले एक कैदी ने जेल प्रहरी को उसके जन्मदिन पर पार्टी दी। इस पार्टी में ना सिर्फ जेल प्रहरी शामिल हुए बल्कि जेल अधिकारी भी जाम पर जाम झलका रहे थे।

कहा जा रहा है कि आजाद हिन्द खंड के प्रभारी शीर्ष अफसर कुलदीप सिंह ठाकुर की जन्मदिन पार्टी बुधवार रात को एक रेस्टारेंट में मनाई गई। यह पार्टी जेल से बाहर आए एक शातिर बदमाश ने आयोजित की थी। यह पार्टी शहर के एक नामचीन रेस्टारेंट में आयोजित की गई थी। पार्टी में जेल अधिकारियों के अलावा जेल प्रहरी और उनके खास जेल से रिहा हुए कैदी भी शामिल रहे। इसमें बंदी राजा पांडे, विशाल दरोगा, सोनिया मनोहर सहित अन्य तीन ऐसे बंदी शामिल थे, जो नई जेल के बताए गए हैं।

रात 11 बजे तक चली पार्टी

बताया जा रहा है कि जन्मदिन पार्टी रात 11 बजे तक चली और कैदी, जेल अधिकारी प्रहरियों ने जमकर जाम झलकाए। इस दौरान खंड प्रभारी कुलदीप के जन्मदिन का केक भी काटा गया है। केक काटने के बाद जाम का दौर चला है। वहीं कुछ जेल अधिकारी कर्मचारी ऐसे थे जो कैदियों के साथ पार्टी मनाए जाने के डर से पार्टी से वापस चले गए।

जेल अधिकारियों को भी नहीं पता कहा दी पार्टी

इस संबंध में जेल अधिकारी भी इस से इंकार कर रहे हैं कि कुलदीप ठाकुर की पार्टी किसी रेस्टारेंट में आयोजित की गई है। उनका कहना है कि ना तो उन्हें स संबंध में कोई जानकारी है और ना हीं यह पता है कि कौन सा कैदी किस अधिकारी कर्मचारी का खास है।

इनका कहना है

जेल अधिकारी का जन्मदिन तो था लेकिन उनकी यह पार्टी किसने और कहां दी इसकी जानकारी नहीं हैं।

मदन कमलेश, जेलर

खाद की किल्लत पर भडक़े मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा, जबलपुर कलेक्टर का मॉडल अपनाओ

कलेक्टर कराते हैं खाद की उपलब्धता की सार्वजनिक जानकारी

जबलपुर/ प्रतिनिधि। पूरे प्रदेश में इन दिनों किसान खाद को लेकर बेहद परेशान हो रहे हैं। किसानों को आसानी से खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की किल्लत का फायदा उठाकर खाद विक्रेता काला बाजारी भी कर रहे हैं। खाद की किल्लत का मामला इतना गंभीर हो गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल प्रदेश भर के कलेक्टरों से सीधे बात की और उन्हें जमकर फटकार भी लगाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना के मॉडल को अपनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि जब पिछले वर्ष से अधिक खाद प्रदेश में उपलब्ध है तो फिर खाद वितरण की समस्या क्यों खड़ी हो रही है। मुख्यमंद्धी ने साफ तौर पर कहा है कि खाद् वितरण व्यवस्था का प्रबंधन करने का जिम्मा सीधे कलेक्टरों का है। नाराज होते हुए मुख्यमंत्री यहां तक कहा कि खाद वितरण में कलेक्टर यदि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि उन्हें जिला चलाना नहीं आता है। ऐसे में कलेक्टर बता दें तो मुख्यमंत्री दूसरी व्यवस्था करेंगे। खाद वितरण को लेकर प्रदेश के कई जिलों में किसान बेहद पेरशान हो रहे हैं। किसान खाद की माँग को लेकर सडक़ों पर उतर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। कई जिलों में किसानों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग भी किया गया है। खाद को लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर खाद की उपलब्धता की समीक्षा करें और इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों से भी सांझा करें ताकि किसानों को वास्तविक स्थिति का पता रहे। कलेक्टर खाद वितरण केन्द्रों को आकस्मिक सत्यापन और निगरानी करें। अतिरिक्त विक्रय केन्द्र की आवश्यकता है तो तत्काल आरंभ करें। खाद की कालाबाजारी को लेकर और अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और नकली खाद आदि से संबंधित 53 एफआईआर दर्ज की गई है। 88 लायसेंस लायसेंस निरस्त और 102 निलंबित किए गए हैं। 406 विक्रय प्रतिबंधित भी किए गए हैं।

जबलपुर - रेलवे अस्पताल में पत्नी-बेटीवाद, जिम्मेदारों ने खुद ही कर ली डाक्टर्स के पद पर नियुक्तियां

जबलपुर/ प्रतिनिधि। पश्चिम मध्य रेलवे के केंद्रीय अस्पताल में परिवारवाद या यूं कहें पत्नी-बेटीवाद जमकर चल रहा है। दरअसल एक मामला सामने आया है, जिसमें इस बात की चर्चा पर जोरों पर है कि पिछले दिनों अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सकीय व्यवस्था दुरुस्त करने के लिये कांट्रेक्ट मेडिकल प्रेक्टीसनर (सीएमपी) के पदों को भरने का काम किया गया, जिसमें अस्पताल के ही मुखिया की पत्नी व बेटी की नियुक्ति कर दी गई।

एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद के खिलाफ हैं और वे अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख भी करते हैं, किंतु पश्चिम मध्य रेल प्रशासन प्रधानमंत्री जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता है। पमरे के जबलपुर के केंद्रीय अस्पताल में हाल ही में की गई सीएमपी की नियुक्तियों में परिवारवाद जमकर हावी रहा। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर (एमडी) डा। अशोक कुमार की पत्नी व बेटी को सीएमपी के पद पर नियुक्ति दी गई।

अन्य दावेदारों में रोष, पीएमओ, रेलमंत्री तक शिकायत की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक सीएमपी के पद पर नियुक्ति की चाह

रखने वाले बड़ी संख्या में डाक्टर्स ने रुचि दिखाई थी और साक्षात्कार में उपस्थित भी हुए थे, किंतु यहां पर अस्पताल के मुखिया के निकटतम रिश्तेदारों को नियुक्ति देने से अन्य लोगों के अवसर में कमी हो गई। जिससे नियुक्ति में असफर रहे केंडीडेट्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) व रेलमंत्री से जबलपुर के केंद्रीय अस्पताल में हुई नियुक्तियों की शिकायतें करने की तैयारी की है। वहीं इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि पमरे मुख्यालय के चिकित्सा विभाग के एक बड़े अधिकारी के एक रिश्तेदार भी सीएमपी पर नियुक्ति हुई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

सीएमपी को इतना मिलता है मानदेय व सुविधाएं

बताया जाता है कि रेलवे अस्पताल में सीएमपी की नियुक्ति होने पर सामान्य एमबीबीएस को 1 लाख प्रतिमाह मानदेय के साथ-साथ साल में 10 छुट्टियां, 1 मुफ्त पास पूरे परिवार का प्रदान किया जाता है, यदि सीएमपी पीजी यानी किसी विधा में विशेषज्ञ है तो उसका मानदेय डेढ़ लाख प्रतिमाह होता है।

परिवारवाद से यह समस्याएं

रेलवे अस्पताल में पत्नि व बेटी की नियुक्ति के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लोगों का कहना है कि यदि एमडी साहब अवकाश पर बाहर जायेंगे, तो उनके साथ पत्नी व बेटी भी अवकाश पर चली जायेंगी, जिससे यहां की चिकित्सा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अस्पताल में डाक्टर्स की भारी कमी

पहले से ही रेलवे अस्पताल में डाक्टर्स व अन्य चिकित्सकीय स्टाफ की भारी कमी चली आ रही है। जो डाक्टर्स हैं, वे भी काफी कम समय अस्पताल में दे रहे हैं। सुबह के समय ही दो या तीन घंटे अपने चेम्बर में मौजूद रहते हैं। सेकंड हाफ में एक-दो डाक्टर्स के अलावा अन्य चिक्तिसकों के चेम्बर बंद पड़े रहते हैं।

इनका कहना- मुझे अस्पताल में नियुक्तियों के संबंध में जानकारी नहीं है। बाद में जानकारी ले कर बता पाऊंगा।

हर्षित श्र।ीवास्तव, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, पमरे, जबलपुर।

पुलिस कर्मियों ने वकीलों के साथ की मारपीट, हाथ, पैर में आई गंभीर चोट, थाना के बाहर अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

जबलपुर/ प्रतिनिधि। दो पुलिस कर्मियों द्वारा देर रात वकीलों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। एक वकील के पैर और हाथ में चोट लगी है। घटना के बाद बड़ी संख्या में वकील मदन महल थाने पहुंचे और संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। वहीं घायल वकील को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया है।

पीड़ित वकील दीपक पटेल ने बताया कि वे एक किराना दुकान के पास खड़े थे। गाड़ी हटाने को लेकर दुकानदार से उनकी कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी सोमनाथ और एक अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और बिना कुछ समझाए उन्हें लाठी से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अमित कोहली की पीठ और उनके हाथों पर भी लाठियां मारीए जिससे उनके हाथ सूज गए और पैर टूट गया। घटना की जानकारी लगते ही अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वकील मदन महल थाने पहुंचे और पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की

मांग पर अड़ गए।

मनीष मिश्रा ने कहा कि कानून के जानकार होने के बावजूद पुलिसकर्मी ने बिना किसी उकसावे के अधिवक्ताओं पर हमला किया है, जो एक गंभीर अपराध है। मिश्रा ने कहा कि घायल अधिवक्ताओं को इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने साफ किया कि दोषी कांस्टेबल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिसकर्मी के खिलाफ अभद्रता की शिकायत मिली है। मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और घायल अधिवक्ता की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण एवं सशक्तिकरण विषय पर उच्च न्यायालय जबलपुर में हुई दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

बालिकाओं के सशक्तिकरण का सामुदायिक पुलिसिंग मॉडल सृजन अभियान की हुई सराहना

जबलपुर/ प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति एवं पोक्सो समिति के तत्वावधान में बालिकाओं के अधिकारों के संरक्षण, सशक्तिकरण एवं चुनौतियों के समाधान विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 30 एवं 31 अगस्त 2025 को मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, जबलपुर में किया गया।

इस कार्यशाला में न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस विभाग, शैक्षणिक जगत, समाजसेवी संगठनों, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा यूनिसेफ के वरिष्ठ पदाधिकारियों, विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य बालिका के अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुआयामी दृष्टिकोण और रणनीतियाँ साझा करना था। कार्यशाला का मुख्य फोकस बाल विवाह, मानव तस्करी, हिंसा, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी और किशोर न्याय प्रणाली पर केंद्रित रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला, सदस्य किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अध्यक्षता में हुआ। उन्होंने कहा कि बाल एवं महिला अधिकारों की सुरक्षा समाज की साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए न्यायपालिका, प्रशासन एवं शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ÷बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा समाज की प्रगति का आधार है तथा सृजन जैसे कार्यक्रम इस दिशा में ठोस परिणाम देने में सक्षम हैं।

हाईकोर्ट जुबेनाइल जस्टिस कमेटी ने सराहा सामुदायिक पुलिसिंग का 'सृजन अभियान'

कार्यक्रम में अन्य न्यायमूर्तियों ने भी सृजन अभियान को सामाजिक चेतना और सामूहिक प्रयास का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कार्यशाला में सृजन अभियान को एक अभिनव और प्रभावी सामुदायिक पुलिसिंग पहल के रूप में सराहा गया।

क्या है ÷सृजन÷ अभियान

सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत पुलिस द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और मलिन बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं के कल्याण के लिए 'सृजन ¬ एक पहल-शक्ति से सुरक्षा की ओर' अभियान का संचालन किया गया। इस अभियान के तहत पुलिस ने कमजोर वर्ग की बस्तियों में जाकर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से बालिकाओं को मौलिक अधिकारों, करियर काउंसलिंग और आत्मरक्षा सहित अन्य प्रशिक्षण दिया। इस अभियान के प्रभाव से बस्तियों में बाल विवाह, घरेलु हिंसा तथा बाल हिंसा में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि इस अभियान को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। ÷सृजन अभियान÷ वर्तमान में प्रदेश के 16 जिलों में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस अभियान को जनता से सकारात्मक सहयोग एवं सराहना प्राप्त हो रही है।

आगामी समय में नवंबर माह तक इसे प्रदेश के सभी जिलों में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से विस्तारित किया जाएगा।

आज ÷सृजन÷ केवल पुलिस का एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। इसने न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त की है, बल्कि भारत में सर्वश्रेष्ठ सामुदायिक पुलिसिंग अभियानों में स्थान भी बनाया है। मध्यप्रदेश पुलिस इस अभियान के माध्यम से कानून-व्यवस्था की संरक्षक से आगे बढ़कर एक संवेदनशील मार्गदर्शक और समाज के भविष्य को सुरक्षित एवं उज्ज्वल बनाने वाली शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है।

बालिकाओं और महिलाओं ने अनैतिक गतिविधियां रोकने में पुलिस का किया सहयोग

'सृजन ¬ एक पहल-शक्ति से सुरक्षा की ओर' अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण के पश्चात पुलिस लगातार इन बालिकाओं से संपर्क में रही और उनसे अपने क्षेत्र और बस्तियों के बारे में जानकारी ली। बालिकाओं ने सहज रूप में समस्याओं के बारे में पुलिस को अवगत कराया और कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने में अपना योगदान दिया। मलिन बस्तियों में रहने वाली बालिकाओं ने प्रशिक्षित होने के बाद अन्य बालिकाओं और महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया और अनैतिक गतिविधियों को रोकने में पुलिस का सहयोग किया। ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां इन बालिकाओं की जागरूकता से पारिवारिक विवादों का निपटारा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगणों ने कार्यशाला की विभिन्न तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता की और महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दीं। विशेषज्ञों ने बाल विवाह एवं मानव तस्करी की रोकथाम, साइबर सुरक्षा, किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा की गुणवत्ता, पुनर्वास और सामुदायिक सुरक्षा पर अपने विचार प्रस्तुत किए। एएसपी श्री जितेन्द्र सिंह ने डिजिटल युग में बालिकाओं की सुरक्षा हेतु साइबर रणनीतियों पर चर्चा की, वहीं यूनिसेफ एवं शौर्य दल की सदस्य युवतियों ने अपने अनुभव साझा कर सृजन की उपयोगिता और असर को प्रत्यक्ष रूप से सामने रखा।

वक्ताओं ने बताया कि बालिकाओं की सुरक्षा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। बीते वर्षो में पुलिस विभाग द्वारा किए गए नवाचारों, जागरूकता अभियानों और त्वरित कार्रवाई की कार्यप्रणालियों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। शौर्य दलों की सक्रियता, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम तथा साइबर सुरक्षा अभियान बालिकाओं को आत्मविश्वास और सुरक्षा का नया भरोसा दिला रहे हैं। कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और कानूनी प्रावधानों, साइबर सुरक्षा, किशोरियों के स्वास्थ्य और यौवनावस्था संबंधी चुनौतियों पर विचार प्रस्तुत किए। शौर्य दीदी और सृजन जैसे सामुदायिक कार्यक्रमों के अनुभव साझा किए गए, जो बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में मदद करते हैं। बालमित्र न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड और पुनर्वास सेवाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बालिकाओं और युवतियों ने अपने अनुभव, संघर्ष और आकांक्षाएँ साझा कीं, जिससे उनकी वास्तविक जरूरतों और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला।

वहीं दूसरी ओर, वक्ताओं ने यह भी स्वीकार किया कि डिजिटल प्लेटफार्म पर अपराधों की बढ़ती चुनौती, पारिवारिक व सामाजिक असमानताएँ तथा त्वरित न्याय की आवश्यकता आज भी गंभीर मुद्दे बने हुए हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए पुलिस, न्यायपालिका, समाज और परिवारों को मिलकर कार्य करना होगा। कार्यक्रम में यह चर्चा भी महत्वपूर्ण रही कि भविष्य में शौर्य दल को सृजन अभियान से जोड़ा जाएगा। इस पहल के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तथा पुलिस विभाग आपसी समन्वय के साथ संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। समापन सत्र में माननीय न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि ÷बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण केवल नीतिगत विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना और सामूहिक प्रयास का परिणाम है। समाज तभी प्रगति करेगा जब उसकी बालिकाएँ सुरक्षित और आत्मनिर्भर हों।÷

नए ऑनलाइन गेमिंग कानून पर हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस

याचिकाकर्ता ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने इसे कौशल आधारित बताया, वैध भी माना है

जबलपुर/ प्रतिनिधि। ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई की। रीवा निवासी क्लबबूम 11 स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ पुष्पेंद्र सिंह ने यह याचिका दायर करते हुए कहा कि नया कानून फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे कौशल आधारित खेलों को भी जुए की श्रेणी में डालकर पूरे उद्योग को अवैध बना रहा है, जो संविधान के खिलाफ है।

उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को केंद्र सरकार ने जो नया ऑनलाइन गेमिंग कानून बनाया है, वह सही नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स (जैसे ड्रीम11 जैसी गेम्स) को पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कौशल आधारित खेल मानकर वैध घोषित किया है।

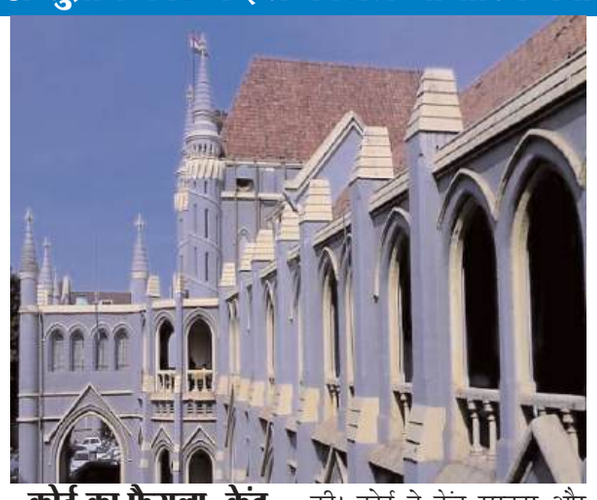

कोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार को नोटिस-

इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।

अन्य राज्यों में भी चुनौती-

इस कानून को मध्यप्रदेश के अलावा कर्नाटक और दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। इन अदालतों ने भी केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल जैन और एडवोकेट अंकित सक्सेना मौजूद थे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने केवल ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर रोक लगाई है जो लोगों को 10 रुपए में 1 लाख जीतने जैसे लालच देकर लत लगाने वाले खेल बना रहे थे। इनसे लोग बर्बाद हो रहे थे। कुछ मामलों में आत्महत्या तक कर चुके हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार से इस पर विस्तृत जवाब मांगा है।

अंतरिक्ष तकनीक में नई उड़ान भरने को तैयार मध्यप्रदेश

स्पेस टैक पॉलिसी-2025 का ड्राफ्ट जारी, सुझाव आमंत्रित

जबलपुर/ प्रतिनिधि। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विजन है कि मध्यप्रदेश को भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाया जाए, जिससे प्रदेश में विकसित स्पेस टैक ईकोसिस्टम सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसी विजन को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश स्पेस टैक पॉलिसी-2025 बनाई गई है। स्पेस टैक पॉलिसी में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और सुशासन में किये जाने के संबंध में भी स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल किये गए हैं। इससे प्रदेश की जनता को सीधे लाभ होगा और प्रदेश भारत की उभरती स्पेस इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित कर सकेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए 'मध्यप्रदेश स्पेस टैक पॉलिसी-2025' का ड्राफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख स्पेस टैक हब बनाना और वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाना है। सरकार ने नागरिकों, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों से इस ड्राफ्ट नीति पर सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिससे यह नीति प्रदेश की आकांक्षाओं और व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप अंतिम रूप ले सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस ड्राफ्ट नीति को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया है। सभी नागरिकों, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शोध संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट पॉलिसी देखने और सुझाव देने हेतु लिंक है और फीडबैक फार्म के लिये लिंक है ।

पॉलिसी ड्राफ्ट के लिए दो हाइलेबल कंसल्टेंसी मीटिंग्स की गई। पहली बैठक ढ्ढ्ढ्ढइंदौरमें हुई। इसमें इसरो, डीआरडीओ, बीईएल, शिक्षाविद और उद्योग जगतके 30 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हुए। मीटिंग में 'मध्यप्रदेश स्पेस टैकः एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज' विषय पर विचार-विमर्श हुआ। दूसरी बैठक बेंगलुरु स्थित क्क्षरु ऑफिसर्स क्लबमें हुई। इसमें इसरो, डीआरडीओ, बीईएल, एसआईए-इंडिया और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के 40 से अधिक विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इनका नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री संजय दुबे ने किया। दोनों मीटिंग्स में आये परामर्शों, विचारों और सुझावों को पॉलिसी ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। पॉलिसी ड्राफ्ट में स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश के पास स्पेस टैक में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएँ हैं। जबलपुर का डिफेंस कॉरिडोर, पीथमपुर का प्रिसिजन इंजीनियरिंग हब, प्रदेश की मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और ढ्ढढ्ढञ्ज इंदौर, ढ्ढढ्ढस्श्वक्र भोपाल एवं क्रख्ञ्ज इंदौर जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक एवं शोध संस्थान प्रदेश को स्पेस टैक सैक्टर में अग्रणी भूमिका दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विशेष रूप से ढ्ढढ्ढञ्ज इंदौर देश का एकमात्र संस्थान है, जो स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम संचालित करता है। स्पेस टैक पॉलिसी को तीन स्तरों–अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम–में विभाजित किया गया है। अपस्ट्रीम में उपग्रह व लॉन्च वाहन निर्माण, प्रोपल्शन, एवियोनिक्स, स्पेस एसेट विकास के लिए विकसित रणनीतियों का समावेश है। मिडस्ट्रीम में मिशन संचालन, लॉन्च सेवाएँ, ग्राउंड स्टेशन, स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट और डेब्रिस मिटिगेशन, जबकि डाउनस्ट्रीम में पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार, नेविगेशन एवं पोजिशनिंग और सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स को शामिल किया गया है। स्पेस टैक पॉलिसी में उद्योग व अकादमिक सहयोग से स्पेस टैक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, उज्जैन में एस्ट्रोफिजिक्स एवं स्पेस साइंस आरएंडडी सेंटर, जो शहर की ऐतिहासिक खगोल-विज्ञान परंपरा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करेगा। पॉलिसी में स्टार्टअप्स व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का स्पेस टैक वेंचर फंड, प्रोटोटाइप ग्रांट, आईपी रिइम्बर्समेंट, इनक्यूबेशन सपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने के लिए नीतियां शामिल की गई हैं। पॉलिसी में स्पेस टैक के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों का समावेश, उन्नत प्रशिक्षण, उद्योग आधारित अप्रेंटिसशिप और फेलोशिप कार्यक्रम शामिल किये गये हैं। प्रदेश में स्पेस टैकइन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने के लिए पॉलिसी में क्लीन रूम्स और टेस्टिंग सुविधाएँ, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, डुअल-यूज़ कंपोनेंट हब, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर, भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए 'अंतरिक्ष विहार' स्पेस एक्सप्लोरेशन पार्क, विद्यार्थियों के लिए 'मिशन कल्पना' कार्यक्रम और इसरो की युविका योजना में भागीदारी के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किये गये हैं।

कैंट विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने विसर्जन घाटों का किया निरीक्षण

जबलपुर।कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने कैंट विधानसभा अंतर्गत मानेगांव तालाब विसर्जन घाट का निरीक्षण सभी पार्षदगणों तथा अधिकारियों के साथ किया तथा सभी घाटों पर उचित व्यवस्था हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य दामोदर सोनी पार्षद निशान झरिया अनुराग दहिया सावित्री शाह संतोषी ठाकुर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

बरगी बांध का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, 15 गेट खोले

निचले इलाकों में अलर्ट

जबलपुर/ प्रतिनिधि। जबलपुर में लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया है। जिससे ग्वारीघाट पर पानी घाटों के ऊपर आ गया है। वहीं बांध के 15 गेट भी खोल दिए गए हैं। जिसे देखते हुए प्रशासन ने घाटों पर दुकान लगाने वालों से तुरंत दुकान खाली करने को कहा है। इसके बाद दुकानदार अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं।

बांध का फुल रिजर्वायर लेवल 422।76 मीटर है। इसके मुकाबले जलस्तर 423।05 मीटर पर पहुंच गया है। बांध में पानी की आवक 1775 क्यूमेक है। जिसे देखते हुए 9 गेट खोले गए थे। इसके बाद 6 गेट और खोल दिए गए हैं। सभी गेट 1।40 मीटर की औसत ऊंचाई तक खोले गए हैं। इनसे कुल 3245 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। कुल निर्वहन 3511 क्यूमेक है। पिछले साल इसी दिन जलस्तर 422।60 मीटर था और लाइव क्षमता 99 प्रतिशत थी जबकि इस साल यह 102।33~ हो गई है।

सायरन बजने के बाद दुकानदारों में हड़कंप-

प्रशासन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। ग्वारीघाट स्थित झंडा चौक के दुकानदार सतीश उपाध्याय ने बताया कि कल भी सायरन बजा था। प्रशासन ने उन्हें तीन घंटे में दुकान खाली करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि उनकी दुकानें अब पानी में डूब सकती हैं। उपाध्याय ने बताया कि पहले भी उनकी दुकानें 10 से 11 दिनों तक डूबी रही हैं। सायरन बजने के एक घंटे बाद पानी आता हैए जिससे उन्हें सामान समेटने का समय मिल जाता है।

पुलिस अलर्ट, लगातार मुनादी-

ग्वारीघाट पुलिस का कहना है कि पिछले एक-दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जलस्तर बढ़ा है। बरगी डैम के गेट खोलने के बाद निचले इलाकों में लगातार अलाउंस कराया जा रहा है। पुलिस ने घाट के दुकानदारों और उनके सामान को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है।

अगले तीन दिन भी बारिश-

मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिन और बारिश का अनुमान जताया है, जिससे जलस्तर चार-पांच फीट और बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी के पास न जाएं और सुरक्षित रहें।

खतरे की स्थिति

लगातार हो रही वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों से आ रहे प्रवाह के कारण नर्मदा नदी उफान पर है। ओंकारेश्वर से आगे खंडवा और खरगोन जिले में बसे नर्मदा किनारे के गांवों और कस्बों के लिए स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बन गई है। यदि वर्षा का सिलसिला जारी रहा और गेटों की संख्या व ऊंचाई और बढ़ाई गई तो नदी का जलस्तर और ऊपर जा सकता है। वर्तमान में नर्मदा नदी का जल स्तर 162,500 तक पहुंच गया है। अगर नदी का जलस्तर 163.980 पर पहुंचा तो खतरे के निशान को पार कर जाएगा।

प्रशासन की तैयारी

गंभीर हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन टीम लगातार निगरानी कर रही है। दोनों जिलों (खंडवा और खरगोन) के पुलिस अधीक्षकों ने सभी थानों को निर्देश दिए हैं कि नर्मदा किनारे जहां-जहां जनसमूह एकत्रित होता है, वहां सुरक्षा बल तैनात रहें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और स्थानीय गोताखोरों को भी तैयार रखा गया है। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को सख्त आदेश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना न हो।

जनता से अपील

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि लोग नर्मदा नदी के किनारे न जाएं। लगातार गेट खुलने से जलस्तर कभी भी अचानक बढ़ सकता है। सावधानी बरतना ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है। नर्मदा के उफान और बांधों की लगातार जलनिकासी ने पूरे नर्मदा तट क्षेत्र को अलर्ट पर ला दिया है। आने वाले समय में नदी का जलस्तर किस ओर करवट लेगा, यह वर्षा पर निर्भर करेगा।

गणेश पंडालों में अवैध बिजली से सुरक्षा खतरे के बीच उत्सव

जबलपुर/ प्रतिनिधि। जबलपुर में इन दिनों गणेशोत्सव का उल्लास चारों ओर बिखरा हुआ है। शहर की गलियों से लेकर बड़े-बड़े मैदानों तक भगवान गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना की गई है और भक्तजनों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मगर इस धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच एक गंभीर खतरा भी मंडरा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है कि शहर के लगभग 25 में से 24 गणेश पंडालों में अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा है। यह तथ्य सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा और बहस का सिलसिला तेज हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन और बिजली विभाग की निगरानी व्यवस्था कहाँ है और इस तरह की लापरवाही से संभावित दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाएगा।

शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थापित पंडालों में दिन-रात रोशनी और सजावट के लिए बिजली की भारी खपत हो रही है। जहां वैधानिक रूप से बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया जटिल और महंगी मानी जाती है, वहीं आयोजकों ने शॉर्टकट अपनाते हुए सीधे लाइन से तार जोड़कर बिजली खींचना शुरू कर दिया। देखने में तो यह छोटा सा काम लगता है लेकिन इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। नंगी तारों के बीच शॉर्ट-सर्किट की संभावना बनी रहती है, और भीड़-भाड़ वाले इन पंडालों में अगर कहीं चिंगारी भड़क गई तो बड़ा हादसा हो सकता है।

बिजली विभाग की टीम ने जब निरीक्षण किया तो पाया कि एक-दो पंडालों को छोड़कर बाकी सभी ने अवैध कनेक्शन किया है। इस खुलासे ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को कठघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह भी है कि हर साल त्योहारों के मौके पर यही स्थिति दोहराई जाती है, फिर भी अधिकारियों की ओर से पहले से कोई ठोस इंतज़ाम क्यों नहीं किए जाते। केवल कार्रवाई का आश्वासन देकर क्या दुर्घटनाओं की आशंका टाली जा सकती है।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएँ दो ध्रुवों में बंटी हुई दिख रही हैं। एक वर्ग का मानना है कि धार्मिक आयोजनों में पंडाल समितियों को प्रशासन की ओर से अस्थायी बिजली कनेक्शन आसानी से और न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि अवैध बिजली का इस्तेमाल सीधे-सीधे चोरी की श्रेणी में आता है और इससे राज्य के राजस्व को नुकसान होता है। यह भी कहा जा रहा है कि आयोजकों को कानून का पालन करते हुए उत्सव मनाना चाहिए, वरना धार्मिक आस्था की आड़ में गैर-कानूनी कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

इस बहस के बीच सुरक्षा का पहलू सबसे अहम है। गणेशोत्सव जैसे अवसरों पर हजारों लोग एक साथ जुटते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पंडालों में दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे माहौल में यदि बिजली की वायरिंग सही तरीके से न की जाए तो दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। पिछले वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों से पंडालों में आग लगने और भगदड़ की खबरें आती रही हैं। जबलपुर में भी लोग इन घटनाओं को याद कर अपनी चिंता ज़ाहिर कर रहे हैं। एक और पहलू यह है कि अवैध कनेक्शन के कारण स्थानीय बिजली आपूर्ति भी बाधित होती है। जब बड़े पैमाने पर बिना अनुमति बिजली खींची जाती है तो आसपास के क्षेत्रों में वोल्टेज गिरने और ट्रांसफॉर्मर जलने जैसी घटनाएँ हो सकती हैं। इसका खामियाजा उन आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है जो नियमित बिल चुकाते हैं और वैधानिक उपभोक्ता हैं।

कानून व्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो यह मामला केवल तकनीकी लापरवाही का नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य का भी है। बिजली चोरी विद्युत अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने और जेल दोनों का प्रावधान है। लेकिन जब मामला धार्मिक आयोजनों से जुड़ा हो तो प्रशासनिक अधिकारी अक्सर सख्ती से बचते हैं। यही कारण है कि आयोजकों का मनोबल बढ़ता है और हर साल वही स्थिति दोहराई जाती है। शहर के कई नागरिकों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन को इस मुद्दे पर तटस्थ और दृढ़ रहना चाहिए। यदि कानून तोड़ा जा रहा है तो कार्रवाई जरूरी है, चाहे वह मंदिर समिति हो, गणेश मंडल हो या कोई बड़ा आयोजक। वहीं कुछ नागरिकों ने यह सुझाव दिया है कि गणेशोत्सव जैसे त्योहारों के लिए अलग से बिजली विभाग को एक खिड़की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अस्थायी कनेक्शन तुरंत और सस्ते दर पर उपलब्ध हो सकें। इससे आयोजक अवैध कनेक्शन लेने से बचेंगे और सुरक्षा भी बनी रहेगी।

गणेश पंडालों में इस बार की स्थिति ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी व्यवस्था में धार्मिक आस्था और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एक ओर भक्तों की भावनाएँ और त्योहार की रौनक है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा और वैधानिकता का सवाल है। इस संतुलन को कायम करना ही असली चुनौती है। यदि प्रशासन समय रहते जागरूकता और सख्ती दोनों को साथ लेकर चले, तो संभव है कि आने वाले वर्षों में जबलपुर जैसे शहरों में त्योहार और भी सुरक्षित और उल्लासपूर्ण ढंग से मनाए जा सकें।

वर्तमान हालात ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध बिजली कनेक्शन केवल तकनीकी गड़बड़ी का मामला नहीं है बल्कि यह समाज के व्यापक हितों से जुड़ा प्रश्न है। चाहे वह सुरक्षा का पहलू हो, कानून का पालन हो या आम नागरिकों के अधिकार–हर दृष्टिकोण से यह मुद्दा गंभीर है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है और क्या इस बार यह व्यवस्था केवल रिपोर्ट और बयानबाज़ी तक सीमित रहती है या फिर वास्तव में कोई सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।त्योहार की चमक-दमक और धार्मिक उत्साह के बीच छिपे इस खतरे ने जबलपुर की जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह केवल एक शहर का सवाल नहीं बल्कि पूरे देश की व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। हर उस जगह पर जहां भीड़, बिजली और आयोजन साथ आते हैं, वहाँ सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। वरना उत्सव के बीच जरा सी चूक कभी भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है।

बदमाश दुर्ग में चोरी करता रहा मोटर साइकलें, अपने पांच साथियों के साथ गिरफ्तार

17 बाइक जब्त

जबलपुर/ प्रतिनिधि। दुर्ग जिले में बाइक चोरी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी शहर में चोरी की बाइक से घूमता था। पेट्रोल खत्म होने पर चोरी की बाइक को वो सड़क के किनारे खड़ी कर के छोड़ देता था। इसके बाद दूसरे बाइक की तलाश में निकल जाता था। आरोपी नाम शुभम श्रीवास है। जो कि मूलतरू जबलपुर का रहने वाला है। यहां दुर्ग में किराए के मकान में रह रहा था।

आरोपी ने पहले अप्रैल 2025 में रिसाली से एक टीवीएस की बाइक चोरी की। पेट्रोल खत्म होने के बाद उसे शराब भट्ठी टंकी मरोदा के पास खड़ी कर छोड़ दिया। 1 मई 2025 को बीआईटी दुर्ग के पास से चोरी की। यह एक्टिवा महाराष्ट्र पासिंग थी। यह गाड़ी अब मारपीट के मामले में वैशाली नगर थाने में जब्त है।

इसके बाद डेढ़ महीने पहले मरोदा सेक्टर से एक बाइक की चोरी की। जब तक पेट्रोल थीए तब तक उस बाइक से दुर्ग।भिलाई में घूमता रहा। पेट्रोल खत्म होने के बाद इस बाइक को भी टंकी मरोदा शराब भट्ठी रोड नर्सरी के पास छोड़कर चला गया। यही सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था। चोरी की बाइक को बेचने की फिराक में नेवई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की बाइक आरोपी ने नेवई बैकुण्ठ धाम मंदिर के पीछे नर्सरी झाड़ी में छुपा कर रखी थी। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी से कुल 7 बाइक जब्त किए गए हैं।

जामुल में भी 10 बाइक जब्त 4 आरोपी गिरफ्तार-

इसी तरह थाना जामुल में नितेश वर्मा की बाइक चोरी की शिकायत पर पुलिस ने एसीसीयू टीम के साथ कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सोहन यादव उर्फ हिन्दी, अविनाश गायकवाड, धनेश्वर साहू और कीर्तिचंद चौहान को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल की और पुलिस को 10 बाइक और 2 बुलेट बाइक बरामद कराई। इन वाहनों की कीमत करीब 5।90 लाख रुपए बताई जा रही है।

घर में बीड़ी बनाकर न्यू कैल्कुलेटर कम्पनी के नाम के पैकिट में नकली बीड़ी पैक कर बेचने वाले के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

275 पैकेट में बीडी के 5 हजार 500 छोटे बंडल एवं 5 किलो की पन्नी में रखी बिना पैक की हुई बीडियॉ, न्यू कैल्कुलेटर बीडी के खाली पैकिट तथा दो पंचिग मशीन जप्त

जबलपुर/ प्रतिनिधि। थाना प्रभारी गोहलपुर श्री रीतेश पाण्डे ने बताया कि दिनांक 02/09/25 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शाहनवाज हुसैन अपने घर नालबंद मोहल्ला में नकली कैलकुलेटर बीडीं बैचने के लिए रखे हुए है। यदि शीघ्र दबिश की जाये तो पकडा जायेगा अन्यथा माल खुर्द बुर्द कर देगा । सूचना पर मुखबिर के बताये अनुसार शाहनवाज हुसैन के घर नालबंद मोहल्ला में दबिश दी घर के बाहर एक व्यक्ति दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पडका गया जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम शाहनवाज हुसैन उम्र 32 साल निवासी नालबंद मोहल्ला थाना गोहलपुर बताया। जिसे सूचना से अवगत कराते हुये पूछताछ करने पर बताया कि घर के अन्दर कमरे में नकली कैलकुलेटर बीडीं रखी है, बींडी घर में ही बनाकर कैलकुलेटर बींडी के खाली पैकेट में डालकर बैचने के लिए रखा हूॅ चैक करने पर कमरे में न्यू कैलकुलेटर बीडी के 40 खाली पैकेट्स तथा 7 बैग/बोरी में कुल 275 पैकेट बीडी प्रत्येक पैकेट में 20 छोटे बीडी के बडंल एवं एक लगभग 5 किलो की पालिथिन में बिना पैक की हुई खुली बीडी रखी मिली। मौके से 7 बैग/बोरी के अंदर 275 पैकेट में 5 हजार 500 छोटे बंडल बीडी के एवं 5 किलो की पन्नी में रखी बिना पैक की हुई बीडियॉ,. कैल्कुलेटर बीडी के खाली पैकिट तथा दो नारंगी रंग की पंचिग मशीन जप्त करते हुये आरोपी शाहनवाज हुसैन के विरूद्ध धारा 63, 65 कापी राईट एक्ट 1957, एवं 103 ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के तहत कार्यवाही की गयी। पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार में लिप्त आरोपियों को चिन्हित करते हुये सभी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

आदेश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर जितेन्द्र सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री मधुर पटेरिया के मार्ग निर्देशन मे थाना गोहलपुर की टीम द्वारा नकली बीडी कम्पनी के नाम के पैकिट में पैक कर बेचने वाले आरोपी को पकडते हुये 275 पैकेट में बीडी के 5 हजार 500 छोटे बंडल एवं 5 किलो की पन्नी में रखी बिना पैक की हुई बीडियॉ, न्यू कैल्कुलेटर बीडी के खाली पैकिट तथा दो पंचिग मशीन जप्त किये गये है।

उल्लेखनीय भूमिका- बीडी घर पर बनाकर कम्पनी के नाम के पैकिट में पैक कर नकली बीडी बेचने वाले को पकडने में उप निरीक्षक अम्बुज पाण्डे, आरक्षक दिनेश दुबे, समरेन्द्र, संजय , आलोक, अभिरंजन, गोपाल, लालजी, महिला आरक्षक दीक्षा की सराहनीय भूमिकी रही।

किसान से रिश्वत ले रहा था समिति प्रबंधक रंगे हाथ पकड़ा गया, जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने दी दबिश

जबलपुर। मंडला के जिला सहकारी समिति मोहगांव में समिति प्रबंधक एक लाख का लोन पास करने के लिए किसान से एक लाख रूपए की राशि मांग रहा था। रिश्वत की यह राशि बाबू के माध्यम से ली जा रही थी। इस मामले की शिकायत आने पर लोकायुक्त दल ने आज छापा मारा और रिश्वत देते हुए रगे हाथों उसे पकड़ा। लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि जिला सहकारी समिति मोहगांव में चार हजार की रिश्वत लेने के आरोप में जिला सहकारी समिति मर्यादितए मोहगांव के समिति प्रबंधक सोहेल खान और दैवेभो पवन सोनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। बताया गया है कि लोन के लिए खाल्हे गिठौरी गांव के नरेंद्र कुमार मसराम ने आवेदन किया था। आवेदन स्वीकृत होने और खाते में राशि आने के बाद भी उसे लोन नहीं दिया जा रहा था। इस पर समिति के बाबू पवन से उसकी बात हुई थी। बाबू ने उसे दस हजार रूपए रिश्वत की मांग की थी। इस पर बाबू से उसका सौदा चार हजार रूपयों पर सेट हुआ था। रिश्वत की मांग को देखते हुए किसान नरेंद्र ने लोकायुक्त से संपर्क किया था। लोकायुक्त टीम ने पीड़ित के की बात पर इस मामले की तस्दीक की और फिर गुरूवार को डिक्कॉय ;रिश्वत की राशि देने के लिएद्ध मंडला के बिछिया चौराहा पर स्थान तय किया गया। लोकायुक्त टीम के मुताबिक चौराहे पर नियत समय पर नरेन्द्र पहुंच गया था। नरेंद्र को निशानी वाले नोट दिए गए थे। मौके पर सोहेल खान के साथ पवन भी आया। पवन के कहने पर उसने उसे जेब में रख चार हजार रूपये सौंपे। उधरए इशारा मिलते ही लोकायुक्त टीम के निरीक्षक उमा कुशवाहा, शशि कला मस्कुले, राहुल गजभिए, जितेंद्र यादव ने उसे दबोच लिया था।

स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक अंकित शर्मा, संपादक शीलू शर्मा द्वारा जवाहर नगर गाली नं. 10 सतना से प्रकाशित तथा अंकित शर्मा द्वारा कोरल ऑफसेट सतना द्वारा मुद्रीत करवाकर प्रकाशित।
समस्त न्याय क्षेत्र सतना होगा। Mail id : udghoshsamay@gmail.com Mob. 7987290705